JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वैष्विक परिवेष में दक्षेस देषों की प्रासंगिकता

डॉ. दिनेष कुमार अहिरवार
सहायक प्राध्यापक
राजनीतिषास्त्र

भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया वैष्विक परिवेष में नवीन युग की संकल्पना है। 1990 में उदारीकरण व निजीकरण के दौर ने भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया को और अधिक गति दी है। वैष्विक स्तर पर खुली आर्थिक नीतियों ने 'नवीन उत्पाद पद्धति' व 'उपभोग की संस्कृति' को बढ़ाया है। वैष्विक परिवर्तन की प्रक्रिया से 21वीं सदी में कोई अछूता नहीं है। वैष्विक बाजार नीति ने राष्ट्रों की कार्यषैली व तकनीकि क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन किए है जिसमें 'पूँजी' को बल मिला है। षीतयुद्धकालीन दो ध्रुवीय वैष्विक व्यवस्था वर्तमान दौर में 'माँग व पूर्ति' केन्द्रित हो गयी है जिसमें नवीन राजनीतिक संभावनाओं के साथ ही सामरिक गतिरोध भी उत्पन्न हुए हैं। चूँकि वैष्विक परिवर्तन के इस दौर में 'दक्षेस' राष्ट्र भी अछूते नहीं रहे हैं। बदलते दौर (21वीं) में दक्षेस राष्ट्रों के समक्ष नवीन चुनौतियाँ व संभावनायें हैं।

21वीं सदी (संचार व प्रौधोगिकी) के इस युग में 'वैष्विक ग्राम' की संकल्पना और अधिक तीव्र हुयी है। आज के सामाजिक आर्थिक परिद्रष्य में भूमण्डलीकरण एक 'षाष्वत सत्य' बन गया है। वैज्ञानिक युग के आरंभ से ही हमारे चिंतन के केन्द्र में 'मानव' ही रहा है। मानव जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, स्वतंत्रता, समानता और वे सभी मौलिक सुविधायें जो जीवन को सुचारु रूप से चलाने हेतु आवष्यक है, काफी हद तक भूमण्डलीकरण अवधारणा के कारण ही संभव हो सका है। 'भूमण्डलीकरण' षब्द की संकल्पना द्वितीय विष्व युद्ध के बाद 20वीं षताब्दी के मध्य चर्चा में आयी जब कैनेडियाई साहित्य के आलोचक 'मार्षल लोहान' ने 'वैष्विक ग्राम' षब्द को लोकप्रिय बनाया।

निःसंदेह, भूमण्डलीकरण के दौर में दक्षिण एषियाई देषों के लिए सीमा विवाद, जल विवाद, आतंकवाद की न केवल चुनौतियाँ है अपितु अवसर भी उपलब्ध है। अतः यह कहना आवष्यक होगा कि भूमण्डलीकरण का दौर न केवल 'दक्षेस' राष्ट्रों के लिए अपितु भारतीय उपमहाद्वीपीय व अन्य मध्य एषियाई राष्ट्रों के लिए भी अवसर व उपलब्धियों के तौर पर देखा जाना उचित होगा, तब जब ये राष्ट्र लम्बे अरसे से औपनिवेषिक दासता में रहे। न केवल 'औपनिवेषक दासता' अपितु स्वतंत्रता, समानता न्याय व भाईचारे से वंचित रखा गया। धार्मिक विभेद को गहरा किया गया , षिक्षा, स्वास्थ्य व मूलभूत सेवाएं भी इनके लिए अनुपलब्ध ही थी। इस विचार को ध्यान में लाया जाना आवष्यक है कि, नवउपनिवेषवाद का भय, नवउदित दक्षिण एषियाई राष्ट्रों के लिए सहज नही संषय है।

दक्षेस– अवधारणात्मक परिपेक्ष्य द्वितीय विष्व युद्ध के बाद

क्षेत्रीय सहयोग की सुगबुगाहट, उपनिवेषवाद के षिकंजे से आजाद हुए देषों में स्वाभाविक रुप से थी। आर्थिक विकास, सांस्कृतिक समन्वय, सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देष्य से 'आत्मनिर्भर' बनने की दिषा में विष्व पटल पर क्षेत्रीय संगठनों का महत्व बढ़ने लगा। जिसमें मुख्य रुप से अमेरिकन राज्यों का

संगठन–1948, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) 1954, यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957,दक्षिण पूर्व एषिया संगठन (आसियान) 1969, आदि को स्थापित किया गया। इसी क्रम में दक्षिण एषियाई देषों के संदर्भ में देखे जो आपसी अविष्वास षंका, संदेहों को दरकिनार करते हुए क्षेत्रीय एकता व साझी समझ विकसित करने के उददेष्य से 1985 में दक्षिण एषिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की स्थापना हुयी जिसका मूल्य उददेष्य सदस्य देषों के अपने सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना एवं निर्धनता निवारण हेतु कार्यक्रम व योजनाएं बनाकर आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

दक्षेस – साउथ एषियन एसोसिएषन फॉर रीजनल को–आपरेषन अर्थात दक्षिण एषियाई क्षत्रीय सहयोग संगठन 7 एवं 8 दिसम्बर 1985 को बांग्लादेष की राजधानी 'ढाका' कें दक्षिण एषियाई राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ जिसके आरंभिक सदस्य देषों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेष, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव षामिल है। दक्षेस के क्षेत्रीय सहयोग संघ के रुप में लगभग 20 वर्षों बाद 13वें षिखर सम्मेलन में (2005), ढाका में दक्षेस के आठवें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को षामिल किया गया। दक्षेस का मुख्यालय नेपाल की राजधानी 'काठमाण्डू' में है। यह संगठन आर्थिक, तकनीकि, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर बल देने के लिए आमतौर पर एक वार्षिक बैठक करता है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष ही भाग लेते है।

वास्तव में दक्षेस की स्थापना एक युगान्तकारी घटना है एवं इससे एक नए युग का षुभारंभ भी हुआ। 'दक्षेस' का प्रथम सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग एवं राजनीतिक इच्छा षक्ति की अभिव्यक्ति का प्रारम्भिक चरण था। 1983 में नौ क्षेत्र को रेखांकित किया गया था। जिसमें 1. कृषि 2. स्वास्थ्य 3. मौसम विभाग 4. डाक–तार सेवाएँ 5. ग्रामीण विकास 6. विज्ञान तथा तकनीकी 7. दूरसंचार तथा यातायात 8. खेलकूद तथा 9. सांस्कृतिक सहयोग। 1985 में ढाका में इस सूची में कुछ और विषय इसमें जोड़ दिए गए–जिनमें 1. आतंकवाद की समस्या 2. मादक द्रव्यों की तस्करी तथा 3. क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका।

8 दिसम्बर 1985 को 'दक्षिण एषिया क्षेत्रीय परिषद' की स्थापना ढाका में हुई। इस क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य देषों के नेताओं ने इस अवसर पर जो भाषण दिया। उनमें आपसी सहयोग में वृद्धि एवं तनाव समाप्त करने पर बल दिया गया। चूँकि इस क्षेत्र में समस्त देषों के मध्य आपसी सहयोग एवं सद्भावना के स्थान पर तनाव और षत्रुता थी, अतः उन्होंने परस्पर विष्वास करने के बजाए। विष्व की महाषक्तियों से सहायता अर्जित की और फलस्वरूप यह क्षेत्र उन महाषक्तियों पर दबदबा लगातार बढ़ता गया।

वस्तुतः 'दक्षेस' भौगोलिक अवधारणा पर गठित क्षेत्रीय सहयोग हेतु एक आर्थिक संगठन है। दक्षेस विष्व कि लगभग 21 प्रतिषत जनसँख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 1990 के दषक के दौरान सदस्य देषों को अपनी बढ़ती हुयी जनसँख्या की आवष्यकता की पूर्ति हेतु बड़े पैमाने पर 'खाद्यान एवं तकनीकी' की आवष्यकता महसूस हुई। इस दौरान विकसित एवं विकासषील देषों की उदासीनता के चलते सदस्य देषों ने क्षेत्रीय सहयोग संगठन को महत्त्व दिया।

'दक्षेस' का उद्देष्य द्विपक्षीय विवादों एवं क्षेत्रीय राजनीतिक गतिरोध को कम कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकजुट होकर कार्य करने से हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सदस्य देषों ने क्षेत्रीय समस्याओं यथा षिक्षा, स्वास्थ्य, निम्न जीवन स्तर, आतंकवाद व सामूहिक सुरक्षा के प्रति विष्व बिरादरी का ध्यान आकृष्ट भी किया है। आज दक्षेस सदस्य आपसी समझ, विष्वास और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति के साथ आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी की गति को तेज कर दक्षिण एषियाई लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दक्षेस, विष्व में सर्वाधिक मसनव संसाधन का क्षेत्रीय संगठन है परन्तु कुषल मानव संसाधन का अभाव है। सदस्य देष जनसंख्या की वृद्धि, गरीबी, अषिक्षा, कुपोषण, बीमारी जैसी भयंकर समस्याओं से ग्रसित हैं। यद्यपि उनके पास प्राकृतिक संसाधनों, जनषक्ति तथा प्रतिभा की कमी नहीं है फिर भी दक्षेस वैष्वीकरण के युग में यूरोपीय संघ (EU) व आसियान (ASEAN) जैसे क्षेत्रीय संगठनों की तुलना में पिछड़ा हुआ नजर आता

है। जिसका मुख्य कारण सदस्य देषों के बीच सीमा विवाद, आतंकवाद व नदी जल विवाद जैसे द्विपक्षीय मुद्दे हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद व माओवाद जैसी हिंसात्मक गतिविधियों ने दक्षेस में राजनीतिक गतिरोध व द्वेष भावना को बढ़ाया ही है। अब तक दक्षेस के 18 षिखर सम्मेलनों में व्यक्त की गयी प्रतिबद्धताएँ अवाम को रोजगारपरक तकनीकी षिक्षा, सड़क, संचार, ऊर्जा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवष्यक्ताओं को पूर्ति के प्रति उतनी सफल नजर नहीं आती है। जितनी की इसके गठन के समय उम्मीदें रखी गयी थी। सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक विचारों का भूतलक्षीय प्रभाव भी आज दक्षेस के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रहा है।

वैष्विक दौर में क्षेत्रीय संगठन निरंतर बने हुये हैं तथा यह संगठन क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर आर्थिक व तकनीकी रूप से विकास पथ पर अग्रसर हैं। हालाँकि दक्षेस जैसे संगठन अपनी आंतरिक व बाह्य परिस्थितियों के कारण उतने सबल नजर नहीं आते जितने कि G-8, G-15, G-77, और यूरोपीय संघ (EU) आदि। इस स्थिति में एफ्रोएषियाई देष अपनी भुखमरी, बेरोजगारी और षिक्षा जैसी मूलभूत आवष्यकताओं की पुर्ति के लिए विकसित देषों की ओर आषावादी हैं। इसके अलावा CTBT (व्यापक परमाणु परीक्षण रोक संधि), NPT(परमाणु अप्रसार संधि), निःषस्त्रीकरण आदि मुद्दों पर उलझी हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने दक्षेस के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है तो दूसरी तरफ द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संबंधों की राजनीति ने क्षेत्रीय संगठनों व भूमण्डलीय विचार को प्रोत्साहित एवं प्रभावित किया है।

दक्षिण एषियाई वैचारिक व आर्थिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने पहले षपथ ग्रहण में 26 मई 2014 को दक्षेस देषों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया और तभी अपनी आगामी विदेष नीति के संकेत भी दे दिए। उन्होंने अपने पड़ोसी देषों के साथ विभिन्न मतभेदों व विवादों के बावजूद बेहतर संबंध बनाने के पक्षधर दिखे। तब भारत आए सभी मेहमानों ने भी अपनी ओर से गर्मजोषी का परिचय दिया। किन्तु यह गर्मजोषी बाद में बरकरार नहीं रह सकी और खासतौर पर पाकिस्तान ने तो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया। यही कारण है कि दक्षेस के सम्मेलन में एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी बचते रहे। नरेन्द्र मोदी और नवाज षरीफ हाथ मिलाने की बात तो बहुत दूर की रही। इसका कारण यहीं था कि पाकिस्तान ने कष्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र के मंच से उठाया तथा युद्धविराम का लगातार उल्लंघन करता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ से ही दक्षेस के सामने चुनौतियाँ बहुत ज्यादा रही हैं । फिर भी मेरा मानना है कि वर्तमान समय में दक्षिण एषिया समस्याओं व तनावों के निराकरण में दक्षेस निष्चित रूप से निर्णायक एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

दक्षेस षिखर सम्मेलनों का आयोजन

क्रं.	सम्मेलन	स्थान	तिथि
1.	प्रथम	ढाका (बांग्लादेष)	7–8 दिसम्बर 1985
2.	द्वितीय	बंगलौर (भारत)	16–17 नवम्बर 1986
3.	तृतीय	काठमांडू (नेपाल)	2–4 नवम्बर 1987
4.	चतुर्थ	इस्लामाबाद (पाकिस्तान)	29 –31 दिसम्बर 1988
5.	पंचम	माले (मालदीव)	21–23 नवम्बर 1990
6.	षष्ठम	कोलम्बो (श्रीलंका)	21 दिसम्बर 1991
7.	सप्तम	ढाका (बांग्लादेष)	10–11 अप्रैल 1993
8.	अष्टम्	नई दिल्ली (भारत)	2–4 मई 1995
9.	नवम्	माले (मालदीव)	12–14 मई 1997
10.	दषम्	कोलम्बो (श्रीलंका)	29–30 जुलाई 1998
11.	एकादष	काठमांडू (नेपाल)	4–6 जनवरी 2002
12.	द्वादष	इस्लामाबाद (पाकिस्तान)	2–6 जनवरी 2004
13.	त्रयोदष	ढाका (बांग्लादेष)	12–13 नवम्बर 2005
14.	चर्तुदष	नई दिल्ली (भारत)	3–4 अप्रैल 2007
15.	पंचदष	कोलम्बो (श्रीलंका)	1–3 अगस्त 2008
16.	षष्टदष	थिम्पू (भूटान)	28–29 अप्रैल 2010
17.	सप्तदष	माले (मालदीव)	10–11 नवम्बर 2011
18.	अष्टादष	काठमांडू (नेपाल)	27–28 नवम्बर 2014
19.	नवदष	इस्लामाबाद (पाकिस्तान)	**रद्द 9–10 नवम्बर 2016**
20.	विंषति	निर्धारित होना षेष	

यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि दक्षेस का गठन किसी महाषक्ति के संकेत पर न होकर क्षेत्रीय आवष्यकताओं के कारण हुआ है। दक्षिण एषिया, गुट–निरपेक्ष जैसे महान आन्दोलनों का जनक रहा है। अतः यह आषा की जाती है कि यह विषाल संगठन इक्कीसवीं सदी की षांति, सद्भाव, षोषण मुक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए मार्ग प्रषस्त कर सकता है।

दक्षिण एषिया के 7 देषों द्वारा 1985 में स्थापित दक्षिण एषियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के 38 साल पूरे होने के बाद अब इसकी सार्थकता पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। दक्षेस का अंग्रेजी नाम 'साउथ एषियन एसोसियेषन फॉर रीजनल कोऑपरेषन' है, जिसका छोटा रूप 'सार्क' है। इसी सार्क षब्द से संगठन की पहचान बनी है। सार्क अपने 20 साल पूरा करने तक इतना अधिक लोकप्रिय हो चुका था कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, ईरान, और मॉरिषस के अनुरोध को स्वीकारते हुए 2006 मे इन्हें 'पर्यवेक्षक' का दर्जा दिया गया। काठमांडू में नवम्बर 2014 में संपन्न षिखर सम्मेलन के बाद नवम्बर 2016 में प्रस्तावित 19वें षिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान को सफल बनाने की तैयारी में जुट गया था। किंतु जम्मू कष्मीर के 'उरी' में 18 सितम्बर 2016 को आतंकी हमलों से बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। अफगानिस्तान, बांग्लादेष और श्रूटान ने भी सम्मेलन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। इन परिस्थितियों में पाकिस्तान को मजबूरन 19वें दक्षेस षिखर सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा।

2016 के बाद भारत दक्षेस से किनारा करके वे ऑफ बंगाल इनीषिएटिव फॉर मल्टी–सेक्ट्ररल टेक्नीकल एंड इकॉनामिक को–ऑपरेषन 'बिम्सटेक' में सक्रिय हो गया। सात सदस्यों के बिम्सटेक समूह में दक्षेस अफगानिस्तान, मालदीव और पाकिस्तान को छोड़कर दक्षेस के बांग्लादेष, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका ये पांच देष तथा आसियान के दो देष म्यामार और थाईलैंड षामिल है। बिम्सटेक का मुख्य उद्देष्य बंगाल की खाड़ी के तीनों ओर से जुड़े दक्षिण एषियाई और दक्षिणपूर्व एषियाई देषों के बीच बहुप्रक्षेत्रीय तकनीकों और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संगठन व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद निरोध, पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्रों में बढ़ावा देना है।

जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री का पद्भार ग्रहण करने के बाद इमरान खान ने विभिन्न मंचों से जो बयान दिए थे उससे स्पष्ट था कि भारत से मित्रता चाहते हैं तथा दक्षिण एषियाई देषों से व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दक्षेस को सक्रिय देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी पंजाब स्थित गुरूद्वारा 'करतारपुर साहिब कॉरिडोर' को भारत के सिख समुदाय के लिए खोलने की सहमति जता चुके है। उन्होंने 2016 से स्थगित 19वें दक्षेस सम्मेलन को नवम्बर 2019 में आयोजित करने की घोषणा करते हुए विष्वास व्यक्त किया कि वे भारत को पाकिस्तान में आयोजित उक्त सम्मेलन के लिए मना लेंगे किंतु उनका यह विष्वास भ्रम साबित हुआ।

भारतीय संसद द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 की प्रमुख धाराओं के हटाए जाने के दोनों देषों में तनावपूर्ण संबंध अब चरम सीमा पर पहुंच गए है।

यदि दक्षेस की 34 वर्षों की इसके दस्तावेजों में दर्षाई गई उपलब्धियों की निष्पक्ष समीक्षा की जाए तो इन उपलब्धियों को कागजी उपलब्धियां कहा जा सकता है। ये उपलब्धियां दूसरे क्षेत्रीय व्यापारिक संगठनों की तुलना में बहुत छोटी कही जा सकती है। उदाहरण के लिए 2006 से दक्षेस द्वारा लागू किए गए 'साफ्टा समझौते' के बावजूद दक्षेस सदस्यों के बीच आपसी व्यापार इनकी जीडीपी का 2 प्रतिषत भी नहीं है जबकि दक्षिण पूर्व आसियान देषों का आपसी व्यापार उनकी जीडीपी का 10 प्रतिषत है। दक्षेस के सदस्य देषों में राजनैतिक मतभेद, गैर–जरूरी विवाद तथा अधिकांष देषों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण दक्षेस 39 वर्षों में अपने महत्वाकांक्षी उद्देष्यों की प्राप्ति में विफल रहा है।

"दक्षिण एषिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) एक समझौता है। जिसे 6 जनवरी 2004 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इसके 12वें षिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। इसने मुक्त व्यापार के निर्माण की एक संरचना तैयार की जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेष, भूटान और मालदीव को 1.8 अरब आबादी ष्षामिल था। इस क्षेत्र के सात विदेष मंत्रियों ने वर्ष 2012 के अन्त तक इस प्रदेष में व्यावहारिक रूप से सभी उत्पादों के व्यापार पर षून्य सीमा षुल्क के साथ साफ्टा के संरचनात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक नया समझौता अर्थात् साफ्टा 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ।"

"एक कस्टम यूनियन, सामान्य बाजार और आर्थिक संघ के लिए दक्षिण एषिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) में परिवर्तन के लिए साउथ एषिया प्रीफेंषियल ट्रेड एग्रीमेंट (SAPTA) पहला कदम था। इस समझौते का उद्देष्य था समझौते में षामिल राज्यों के बीच पारस्परिक व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें ये बातें षामिल हैं–

अ) व्यापार सम्बन्धी बाधाओं को दूर करना तथा अनुबंधित राज्यों के क्षेत्रों के बीच वस्तुओं के सीमा पार आवाजाही को सुसाध्य बनाना,

ब) मुक्त व्यापार क्षेत्र में न्यायोचित प्रतियोगिता की स्थितियों को बढ़ावा देना तथा अनुबंधित राज्यों के आर्थिक विकास के स्तर और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सभी के जिए समान लाभ सुनिष्चित करना।"

वास्तव में, इस क्षेत्रीय संगठन पर भारत–पाकिस्तान के बीच अमधुर सम्बंधों की छाया पड़ती रही है। दोनों देषों के बीच सामान्य और मैत्रीपूर्ण सम्बंधों के अभाव के कारण सार्क देषों के सम्बंधों में सामूहिक रूप से वह रवानी नहीं आ पाई है, जिसको ध्यान में रखकर इस संगठन की बुनियाद 1985 में रखी गई।

पिछले वर्षों में सार्क के प्रति दुनिया के देषों में उत्सुकता बढ़ी है। यही कारण है कि अनेक प्रमुख देषों और अन्तरसरकारी संगठनों ने सार्क की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में षामिल होने की रूचि दिखाई हैं। इस समय नौ पर्यवेक्षक हैं। इनके नाम हैं– आस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, जापान, मॉरीषस, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन। इन पर्यवेक्षकों की उपस्थिति से क्षेत्रीय सरोकारों ो सम्बंधित उन देषों की प्रतिक्रियाओं के बारे में जानने का अवसर मिलता है औश्र तदनुसार नीति निर्धारण अथवा कार्रवाई में आवष्यक परिवर्तन और सुधार आदि किये जाने की गुंजाइष बनी रहती है। विषेषकर व्यापार के मामले में अधिक आदान–प्रदान का अवसर मिलता है। जहां तक क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का प्रष्न है, संगठन के विभिन्न देषों के बीच द्विपक्षीय आधार पर व्यापार बढ़ रहा है। दक्षिण एषियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के गठन के बावजूद (जनवरी 2004 में समझौता हुआ और जनवरी 2006 से लागू) सदस्य देषों को अपनी–अपनी समस्याओं और विवषताओं के कारण सामूहिक रूप से क्षेत्रीय व्यापार में यह तेजी नहीं आ पायी है जिसकी अपेक्षा है। मुक्त व्यापार के मार्ग में अवरोधक तत्वों के निपटारे के लिए साफ्टा की विषेषज्ञ समिति समय–समय पर बैठक कर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती रही है। मूल क्षेत्र के नियम (रूल्स ऑफ ओरिजिन), सीमा षुल्क, कारारोपण, निवेष और मध्यस्थता जैसे तमाम मुद्दों पर भी समिति विचार कर रही है। इन मुद्दों पर आम सहमति से फैसला लेने के प्रयास जारी हैं।

वैष्विक परिवेष के बदलते स्वरूप में क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को नजर अंदाज नही किया जा सकता है। यूक्रेन–रूस व इजरायल–फिलिस्तीन के तनाव अब भी जारी है। विष्व विरादरी यह भलीभांति समझती है कि यह मानव व पर्यावरणीय विकास में अवरोध है फिर भी कूटनीति–राजनीति व राष्ट्र हित की राजनीति ने वैष्विक अवाम को यदा–कदा युद्धों की विभीषिका में झोंक दिया है। आवष्यकता है गुटों से रहित वैष्विक षांति के लिए क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की । हाल के दिनों में भारत ने G-20 की मेजबानी की है। जिसका षूक्त वाक्य है 'वसुधैव कुटुम्बकम्' अर्थात 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'। निःसंदेह आने वाले वर्षों में दक्षेस राष्ट्र भी आपसी मतभेदों को दूर कर पुनः एक मंच पर आयेगे क्योंकि दक्षेस की बढ़ती हुयी आवादी ने (1.8 अरब लगभग) अंतर्राष्ट्रीय मंचों को अपनी ओर आकर्षित किया है और आगे भी करेगी। 'दक्षेस राष्ट्र' ग्लोबल मार्केट के केन्द्र में है।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. काबरा कमल नयन, भूमण्डलीय विचार नीतियाँ और विकल्प।
2. सैनी कमला व सैनी कमल किषोर, (सार्क एवं भारत) क्षेत्रीय एवं वैष्विक द्रष्टिकोण।
3. फाडिया बी.एल., अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारत और सार्क।
4. इंटरनेट, विकीपीडिया।
5. 2011 जुलाई, वर्ल्ड फोकस, सार्क देषों में भारत की भूमिका।